मेट्रो हास्पिटल ने लूट के पैसे लौटाये

म मो (फरीदाबाद) - आप प्रतिदिन समाचार पत्रों में प्राइवेट हस्पतालों की लूट की खबरें पढ़ते होंगे। ऐसी ही लूट फरीदाबाद के लुटेरे हस्पताल ने एक बच्चे के साधारण से आपरेशन के बावन हजार रुपये वसूल लिए। जो आपरेशन दस पंद्रह हजार में होना चाहिए था उसके बावन हजार रुपये वसूल लिए वो भी हरियाणा सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए निर्धारित रियायती दरों पर। लेकिन बिना किसी शोर शराबे के हस्पताल से लूटा गया पैसा वापिस वसूल करना एक आश्चर्य से कम नही है।

मामला पलवल के गाँव औरंगाबाद निवासी आनंद सिंह के पुत्र जयदीप के अपेंडिक्स की बीमारी के आपरेशन का है। 31 अगस्त को उपायुक्त कार्यालय फरीदाबाद में कार्यरत आनंद सिंह के नौ वर्षीय पुत्र को पेट दर्द की शिकायत के चलते पलवल में बच्चों के डाक्टर अनिल मालिक को दिखाया उन्होंने बच्चे की कुछ जांच करवाई तो बच्चे को अपेंडिक्स का पता चला जिस पर उन्होंने किसी सर्जन की सलाह लेने की सलाह दी। इस पर उन्होंने अपने पुत्र को पलवल में ही गोयल नर्सिंग होम के सर्जन डाक्टर नरोत्तम गोयल को दिखाया गया उन्होंने जांच रिपोर्ट व बच्चे की जांच के उपरांत उसे अपेंडिक्स होने की पुष्टि करते हुए तुरंत आपरेशन करवाने को कहा। तुरंत आपरेशन की बात सुनकर वे बच्चे उसी दिन रात दस बजे मेट्रो हास्पिटल में ले आये वहां इमरजेंसी में ड्यूटी डाक्टर को पलवल में करवाई गई सभी जांच रिपोर्ट अल्ट्रा साउंड रिपोर्ट सहित दिखा दी। ड्यूटी डाक्टर ने सर्जन से फोन पर आपरेशन हेतु बात की लेकिन सर्जन डाक्टर ने आपरेशन से पहले फिर वे ही जांच पुनः करवाने को कहकर अगले दिन देखने को कह दिया। अब हास्पिटल का जांच के नाम पर लूट का खेल शुरू हो गया जो आपरेशन तुरंत होना चाहिए था उसे चौबीस घंटे तक केवल बिल बनाने के चक्कर में नही किया गया जबकि अपेंडिक्स फटने से शरीर में विषाक्तता का पूरा खतरा रहता है। अगले दिन आपरेशन से पहले ही जांच व डाक्टर की विजित के नाम पर ही तीस हजार रुपये का बिल बना दिया आपरेशन के साढे उन्नीस रुपये जो हरियाणा सरकार इस आपरेशन के लिए राशि निर्धरित अलग। इस प्रकार कुल मिलाकर बिल बावन हजार रुपये तीन दिन के वसूले लिए गए उसपर ये तुर्रा अलग कि इस आपरेशन का खर्चा तो बयासी हजार से कम नही होता ये तो हरियाणा सरकार द्वारा निर्धारित पैकेज के कारण हैं।

इस बिल को जब आनंद सिंह ने अपने विभाग में भुगतान हेतु प्रस्तुत किया तो उसे नियमानुसार केवल बीस हजार रुपये के भुगतान हूने की बात बताई इसपर वो मेट्रो हॉस्पिटल गया और अधिक बिल को ठीक करने को कहा लेकिन उसे वहां से इधर उधर की बात करके टरका दिया। हारकर उसने अपने विभाग से बीस हजार के भुगतान के लिए बिल प्रस्तुत करते हुए एक शिकायत उपायुक्त देते हुए बकाया राशि के भुगतान को हॉस्पिटल या सरकार से करवाने के लिए दिया जिसे उपायुक्त कार्यालय द्वारा जाँच के लिए सिविल सर्जन को भेज दिया।

सिविल सर्जन कार्यालय में मामले की जांच उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी को सौंपी गई जिन्होंने पहली ही पेशी में मेट्रो होस्पिटल की बदमाशी को पकड़ लिया तथा मेट्रो हॉस्पिटल से गए डाक्टर को नियमों का आइना दिखाते हुए अधिक वसूली गई राशि को वापिस करने को कहा इस पर अपनी चोरी को पकडे जाने पर फंसने के डर से मेट्रो हॉस्पिटल ने तुरंत फालतू की राशि तीस हजार वापिस कर दी।

नगर निगम में हरामखोरी व रिश्वतखोरी का नंगा नाच.....

पेज एक का शेष

ने पूरी गुंडागर्दी दिखाते हुए पड़ोसी मकान की दीवार के साथ तक सटाकर बेसमैंट खोद डाला, उसने तनिक भी नहीं सोचा कि उसके इस अवैध काम से पडोसी के मकान की दीवार दरक कर गिर सकती है। बिल्डर की इस गुंडागर्दी के विरुद्ध पड़ोसी प्लॉट धारकों ने निचले कर्मचारियों से लेकर निगम के ज्वायंट कमिश्नर व एडिशनल कमिश्नर तक न केवल टेलीफोन पर बल्कि व्यक्तिगत रूप से मिलकर लिखित शिकायत दिये जाने के बावजूद बिल्डर का अवैध निर्माण कार्य पूरे जोरों पर है। एक शिकायतकर्ता शिव कुमार जोशी ने बताया कि संबंधित ज्वायंट कमिश्नर ने तो अपनी लाचारी, व्यक्त करते हुए यहां तक कहा कि क्या करें नीचे वाले सुनते ही नहीं। यदि ऐसा है तो यह अराजकता की परिकाष्ठा है। इसके अलावा यह अधिकारियों की कमजोरी एवं मिलीभगत का संकेत भी देता है।

मजदूर मोर्चा ने इस बाबत संबंधित एसडीओ ओमप्रकाश मोर से पूछा तो उन्होंने बताया कि वे शिकायत मिलने पर अभी-अभी मौका मुआयना करके आये हैं। मुआयने के बाद उन्होंने बिल्डर को हिदायत दी है कि वह नियमानुसार प्लॉट में जगह छोड़कर ही बेसमेंट बनाये। मोर के अनुसार उसने आगे-पीछे जगह छोड़ने हेतु दीवार बना दी है जिसमें वह शाम तक मिट्टी भरवा देगा वरना वे उसका सारा निर्माण तुड़वा देंगे। लेकिन खबर लिखे जाने यानी शनिवार शाम तक न तो उसने मिट्टी भरी, न ही काम रोका, बल्कि काम की गति और बढ़ा दी। मोर ने यह भी बताया था कि बेसमैंट बेशक उसके नक्शे में नहीं है लेकिन यह कम्पाऊंडेबल है जिसे बनाना उनका हक है।

इस क्षेत्र में पहले ढाई मंजिला मकान बनाना ही संभव था लेकिन अब सरकार ने चार मंजिला बनाने की इजाजत दे दी है। अब तमाम बिल्डर बेसमैंट समेत 6 मंजिला इमारतों का निर्माण तो कर ही रहे हैं, परन्तु इतनी भारी इमारतों के लिए मिट्टी की टेस्टिंग जैसे कानून का घोर उल्लंघन भी कर रहे हैं। रिश्वत डकारे बैठे तमाम अधिकारी आंखें मूंद चुपचाप किसी बड़ी दुर्घटना को न्यौता दे रहे हैं।

हफ्तों पद खाली रहने के.....

पेज एक का शेष

पर सीधा प्रहार है। चलो प्रहार तो उन्होंने कर दिया, अपने मातहतों की खिंचाई भी खूब जोर से कर दी, परन्तु नगरवासी अब यह देखना चाहेंगे कि वे क्या नया करती हैं। चहुं ओर फैली इस अव्यवस्था को बर्दाश्त नहीं करेंगी तो क्या करेंगी? हरामखोरी व रिश्वतखोरी में आंकठ डूबे इस पूरे प्रशासन को वे किस तरह पटरी पर लायेंगी। राजनेताओं के आशीर्वाद एवं संरक्षण में पलते तमाम अधिकारियो को वे कहां तक अवैध कब्जे व निर्माण कार्यो से कैसे रोक पायेंगी, यह तो समय ही बतायेगा। दरअसल, निगम के तमाम अधीनस्थ अधिकारी अपने आप को स्थाई जबकि कमिश्नर तथा ज्वाइंट कमिश्नरों को अस्थायी मानते हैं। यह हकीकत भी है। निगम में तैनात आईएएस व तीन एचसीएस तो आते जाते रहते हैं जबकि निगम द्वारा भर्ती तमाम अधिकारी व कर्मचारी कहीं जाने वाले नहीं हैं। उन्होंने यहीं से नौकरी शुरू की है और यही समाप्त करेंगे। इसलिये वे आईएएस व एचसीएस अफसरों की कोई खास परवाह नहीं करते। वे सोचते हैं कि ये अफसर दो चार महीने भोंक-भोंक कर रह लेंगे, इसलिये वे चुपचाप उनकी डांट फटकार एक कान से सुन कर दूसरे कान से निकाल देते हैं। अनीता यादव नगर निगम में काफी समय तक ज्वायंट कश्मिनर भी रह चुकी हैं, इसलिये उनसे कुछ छिपा हुआ नहीं है। वे निगम प्रशासन की नस-नस से वाकिफ है। यदि करना चाहेंगी तो बहुत कुछ कर भी सकती है।

सुधी पाठकों से अपील

31 वर्षों से 'मज़दूर मोर्चा' वैकल्पिक मीडिया के तौर पर अपने सुधी पाठकों को वह समाचार, विचार एवं जन उपयोगी सामग्री प्रस्तुत करता आ रहा है जिसे अन्य मीडिया छिपाने का प्रयास करता है। सुधी पाठक इतना तो समझ ही गये होंगे कि यह छोटा सा अखबार किसी भी राजनीतिक अथवा व्यवसायिक धड़े से जुड़ा नहीं है। जनहित में जो भी प्रकाशित करने लायक सामग्री हो पाती है उसे लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है।

बिना विज्ञापनों के, केवल पाठकों के सहयोग से चलने वाला यह छोटा सा अखबार आपको और अधिक बेहतर व निरंतर सेवा देता रहे इसके लिये आप से निवेदन है कि इसमें अपना आर्थिक सहयोग अवश्य प्रदान करें। 'मज़दूर मोर्चा' नियमित रूप से खरीदकर पढ़ने वाले पाठक तो अपना योगदान दे ही रहे हैं, इलेक्ट्रोनिक माध्यम से अखबार पढ़ने वाले पाठकों से विशेष अनुरोध है कि वे भी इसमें अपना आर्थिक सहयोग प्रदान करें। वार्षिक सहयोग के तौर पर 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये की धनराशि सामर्थ्य अनुसार 'मज़दूर मोर्चा' के निम्नलिखित खाते में डाले जा सकते हैं।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में
खाता संख्या : 451102010004150
IFSC CODE : UBIN0545112

घर बैठे प्राप्त करें मज़दूर मोर्चा

आज ही अपने हॉकर से कहें, कोई दिक्कत हो तो शर्मा न्यूज एजेंसी से फोन नं 9811159238 पर बात करें। बल्लभगढ़ के पाठक अरोडा न्यूज एजेंसी से 9811477204 पर बात करें।

अन्य बिक्री केन्द्र :

1. **आनंद मैगजीन सैंटर केसी रोड, एनएच-5**
2. **प्रिंट फोर्ट, टेलीफोन एक्सचेंज के सामने नेहरू ग्राउंड**
3. **रेलवे बुक स्टाल ओल्ड रेलवे स्टेशन**
4. **एनआईटी रेलवे स्टेशन के बाहर बाटा चौक पुल के नीचे**
5. **राम खिलावन बल्लबगढ़ बस अड्डा पुलिस चौकी के सामने**
6. **हितेश ग्रोवर सैक्टर 29 पेट्रोल पम्प के पास**
7. **जितेन्द्र, बाटा सैंटर - 9971064207**

गतांक की चीर-फ़ाड़

महिलाओं का सबरीमाला मंदिर में प्रवेश वर्जित और स्मार्ट सिटी का कोरा ढिंढोरा

डॉ. जुगल किशोर गुप्ता

मजदूर मोर्चा के 6-12 जनवरी 2019 के अंक में राष्ट्रीय, क्षेत्रीय व स्थानीय महत्वपूर्ण मुद्दों पर अनेक समाचार प्रकाशित हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सदैव असहज प्रश्नों का सामना करने से हिचकते हैं, इसलिए उन्होंने कभी भी प्रेस कान्फ्रेंस नहीं बुलाई। वे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) परस्त पत्रकार, भाजपा को कवर करने वाले पत्रकार या ऐसे पत्रकार को इंटरव्यू देना पसंद करते हैं जिसके साथ वह सहज महसूस करते हैं कि कोई आलोचनात्मक प्रश्न नहीं पूछे जायेंगे। वे हर महीने 'मन की बात' करते हैं लेकिन वहां भी श्रोताओं द्वारा पूछे गए प्रश्न प्रायोजित होते हैं।

मोदीजी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब प्रख्यात पत्रकार करण थापर ने 2007 में उनसे इंटरव्यू में सटीक व आलोचनात्मक प्रश्न पूछा था कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने गुजरात कांड पर लिखित टिप्पणी की थी कि वह गुजरात सरकार में भरोसा खो चुकी है और आप आधुनिक समाज के नीरो हैं, जो असहाय बच्चों व महिलाओं को जलाते समय दूसरी तरफ देखने लगते हैं। इस पर मोदीजी चिढ़कर दो-तीन मिनट की बातचीत के बाद उठकर चले गए, और कहने लगे कि उन्हें आराम करना है और पानी चाहिए। 'वह इंटरव्यू जिसमें पानी मांग गए थे, मोदी के जरिए इस इंटरव्यू के दौरान हुई बातचीत से पाठकों को रूबरू कराया गया है। मोदीजी करण थापर से इतना नाराज हो गए कि उन्होंने 11 वर्ष बाद भी करण थापर को माफ नहीं किया और मोदीजी ने अपने मंत्रियों और भाजपा के सभी प्रवक्ताओं से कह दिया कि वे करण थापर के शो में न जाएं। आश्चर्य है कि प्रैस काउंसिल अथवा किसी भी मीडिया ने मोदीजी के सामने इस मामले को नहीं उठाया।

एनएनआई की सीईओ और सम्पादक स्मिता प्रकाश के साथ मोदीजी के इंटरव्यू को लगभग सभी टीवी चैनल ने लाईव प्रसारित किया और अखबारों में भी छापा। जिन्होंने भी इस इंटरव्यू को देखा या पढ़ा उनकी सटीक प्रतिक्रिया थी कि यह इंटरव्यू प्रायोजित था। मोदीजी जिस ढंग से प्रश्नों का जवाब दे रहे थे उससे ऐसा लगा रहा था कि जैसे उन्हें सवाल पहले से पता थे। इस पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने पत्रकार को दब्बू कहा तो मोदीराज में डरे हुए चुप बैठे मीडिया के तमाम पत्रकार व नेता बढ़-चढ़कर राहुल की आलोचना करने लगे। 'राहुल गांधी ने पत्रकार को दब्बू कहा तो इसमें गलत क्या है - मोदीराज में डरी हुई मीडिया को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए' में मीडिया की निष्पक्ष भूमिका पर चर्चा करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। गौरतलब है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प व मोदीजी दोनों मीडिया पर अपना अंकुश चाहते हैं। अमेरिका का मीडिया तो पूर्णरूप से स्वतंत्र और ताकतवर है जो ट्रम्प की नीतियों की आलोचना करने से पीछे नहीं हटता जबकि हमारा मीडिया मोदीजी के भय के कारण नतमस्तक है जो प्रजातंत्र की सफलता के लिए घातक है।

'2014 में लूट या 2018 में टूट: 2019 के सामने चुनौतियां' में 2019 में देश के सामने खड़ी चुनौतियों का विश्लेषण किया गया है। सबसे बड़ी चुनौती भ्रष्टाचार की लूट और सामाजिक तौर पर देश की टूट के बीच से किसी एक को चुनने की ही है। दूसरी, एक तरफ सत्ता और पार्टी (कांग्रेस) का संतुलन है तो दूसरी तरफ सत्ता (मोदीजी) का एकाधिकार है। जहां प्रधानमंत्री के सामने ना पार्टी (भाजपा) का कोई महत्व हे, ना ही सांसदों का और न ही कैबिनेट मंत्रियों का। तीसरी, नोटबंदी, जीएसटी व राजकोषीय घाटा आदि के कारण चक्रव्यूह में फंसी अर्थव्यवस्था को संभालने की। बेरोजगारी और किसानों की बदहाली की समस्या का भी हल निकालने की चुनौती है।

मोदी सरकार की सौभाग्य योजना के तहत देशभर में घरों में लगे बिजली के मीटर बदलकर 'स्मार्ट मीटर' लगाये जायेंगे। कहा जा रहा है कि इन स्मार्ट मीटर को लगाने की एवज में उपभोक्ताओं से कोई चार्ज नहीं लिया जायेगा। ध्यान देने योग्य है कि ये मीटर चीन से खरीदकर बिना गुणवत्ता की जांच किए घरों में लगाये जायेंगे क्योंकि इन स्मार्ट मीटर की सप्लाई भारत सरकार की एजेंसी ईईएसएस कर रही हैं लेकिन ये मीटर उपभोक्ताओं के हित में नहीं बल्कि मीटर बनाने वाली व आपूर्ति करने वाली एजेंसियों तथा अधिकारियों को इनसे फायदा होगा, जिसका 'आप इस मोदी घोटाले के बारे में जानकार हैरान हो जायेंगे' में कच्चा चिट्ठा खोला गया है। फरीदाबाद विद्युत विभाग का कहना है कि कुछ वर्षो बाद स्मार्ट मीटर का किराया उपभोक्ताओं से वसूला जायेगा।

10 वर्ष से 50 साल की महिलाओं का सबरीमाला मंदिर में प्रवेश वर्जित करने की सदियों पुरानी गैर बराबरी की रूढ़ीवादी परम्परा के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के पक्ष में फैसला दिया था जिसको केरल सरकार ने लागू करने के लिए प्रयास किया तो भाजपा व कांग्रेस दोनों ने इस निर्णय का विरोध करना शुरू कर दिया। 'स्त्री की कोख का सहारा लेने वाले देवता को स्त्रियों से डर क्यों लगता है?' में महिलाओं के अधिकारों के प्रति महिलाओं के जागरूक होने की आवश्यकता की समीक्षा की गई है। विडम्बना है कि महिलाओं की बराबरी व सशक्तिकरण करने की बात करने वाली भाजपा, मोदी सरकार तथा संघ परिवार सभी इस निर्णय का विरोध कर रहे हैं और धर्म की आस्था के नाम पर महिलाओं को ही महिलाओं के विरुद्ध लड़ाया जा रहा है।

मोदी सरकार देश भर में रैलियों में स्मार्ट सिटी का ढिंढोरा पीट रही है और अरबों रुपया खर्च कर रही है, परन्तु धरातल पर उन शहरों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है, जिसका 'स्मार्ट सिटी का ड्रामा न किसी को समझा है न इच्छा शक्ति' में उजागर किया गया है। फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी घोषित हुए लगभग दो साल बीत चुके हैं लेकिन आज तक स्मार्ट सिटी के नाम पर कोई निर्माण कार्य पूरा नहीं किया गया है। शहर में इस समय 14 लाख आबादी के लिए केवल 47 पब्लिक टॉइलेट है जबकि सैक्टर-21डी व भगत सिंह चौक एनआईटी पांच में बने स्मार्ट टॉइलेट खोले ही नहीं गए है। इसलिए शहर में लोग खुले में शौच करते हैं और जगह-जगह कूड़े के ढेर दिखाई देते हैं।

'दिहाड़ीदार डीजीपी सन्धू का पुलिस में नियमित भ्रष्टाचार समाप्त करने का दावा' में डीजीपी बलजीत सिंह सन्धू के पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार नियंत्रण के दावे का भंडाफोड़ किया गया है। वास्तव में निम्न स्तर पर रिश्वतखोरी अधिकतर उच्च स्तर के अधिकारियों व नेताओं की फरमाईश पूरी करने के लिए की जाती है। मुख्यमंत्री खट्टर ने आगामी चुनावों के मद्देनजर चुनावी फायदा लेने और अपने इशारे पर मनमाफिक काम करवाने के लिए सेवानिवृत्त डीजीपी सन्धू को बरकरार रखा है। हालांकि सन्धू का इस पद पर कोई वैधानिक अधिकार नहीं है इसलिये खट्टर के इशारे पर नाचना उसकी मजबूरी है।

'चिकित्सा के लिए नहीं, लुटाने के लिए बजट है' के जरिए स्थानीय बी.के. अस्पताल, सिविल अस्पताल पलवल तथा गांव कुरारी स्थित सामुदायिक हैल्थ सैंटर में अस्पताल में तैनात फार्मेसिस्ट सांगवान, स्टाफ सप्लाई करने वाली फर्म मार्शल सिक्युरिटी सर्विसेज के मालिक महेन्द्र दीक्षित तथा तत्कालीन कार्यवाहक सीएमओ डा. वीर सिंह सहरावत की मिलीभगत से किए गए घोटालों का पर्दाफाश किया गया है। ये घोटाले मुख्यमंत्री खट्टर के भ्रष्टाचार मुक्त शासन के दावे की खुली चुनौती है।

'इंडियन एक्सप्रेस और टेलीग्राफ का फर्क में जनसत्ता के नारे 'सबकी खबर ले, सबको खबर दे' तथा खबर लेने के मामले में हम किसी को नहीं छोड़ते के दावे का इंडियन एक्सप्रेस में सेल्युलर जेल के जिस सेल में वीडी सावरकर को रखा था वहां बैठकर मोदीजी ने हिन्दुत्व विचारक सावरकर को श्रद्धांजलि देने की फोटो छापने के संदर्भ में विरोधाभास को स्पष्ट किया गया है। इसमें सावरकर के बारे में यह नहीं बताया गया कि सेल्यूलर जेल से बाहर आने के लिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार से अपील की थी और वे स्वतन्त्रता आंदोलन से पीठ दिखाकर भाग खड़े हुए थे। यह इतिहास को तोड़-मरोड़कर प्रस्तुत करने के प्रयास का ओर एक और कदम है।

स्मिता प्रकाश से प्रधानमंत्री मोदी के इंटरव्यू को मीडिया द्वारा महान इंटरव्यू बताने पर 'महान इंटरव्यू', बरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए हरियाणा सरकार की योजनाओं 'एचएसएफसी एक्जाम' तथा करण थापर से मोदीजी के इंटरव्यू के दौरान नाराज होकर पानी मांगने के बहाने उठने पर कार्टूनों द्वारा उपयुक्त तंज कसा गया है।